

आज का बीड बंद रहः उबाळे, धांडे, बांगर, सरवदे ने दी जानकारी

बीड (प्रतिनिधि)
उमाकिरण संकुल में कोचिंग क्लास की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में फरार चल रहे प्रो. विजय पवार और प्रशांत खाटोकर को बीड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार (दिनांक ३०) को घोषित किया गया बीड बंद अब रह कर दिया गया है, यह जानकारी स्वाभिमान संगठन के जिला अध्यक्ष प्रो. सचिन उबाळे, राष्ट्रवादी युवक

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अंड. महेश धांडे, राष्ट्रवादी पार्टी के युवा नेता शिवराज बांगर, और वंचित बहुजन अघाड़ी के जिलाध्यक्ष अजय सरवदे ने दी।
दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आंदोलन शुरू किया था और समाज में आक्रोश की लहर फैल गई थी। इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर सोमवार को बीड बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि, बीड पुलिस अधिकक्ष नवनीत

काँवत के मार्गदर्शन में तीन टीमों गठित की गईं और स्थानीय क्राइम ब्रांच की तत्परता से रविवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कारण सोमवार का बीड बंद अब रह कर दिया गया है, यह जानकारी आयोजकों की ओर से दी गई। प्रो. उबाळे, अंड. धांडे, शिवराज बांगर, अजय सरवदे के साथ-साथ सुरज चुंगडे, प्रो. पंडित तुपे, राजेंद्र आमटे, अनुरथ वीर, अंड. संगीताताई धसे, अमोल वडतिले और सोमेश कदम ने भी बंद रह करने की पुष्टि की।

वक्फ संशोधन कानून केंद्र सरकार को वापस लेना ही होगा- मौलाना खालिद सफुल्लाह रहमानी का चेतावनीपूर्ण बयान

बीड में वक्फ बिल के खिलाफ
जन विरोध सभा में उमड़ा जनसैलाब

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव,
प्रवक्ता सहित देशभर के धर्मगुरुओं की भारी मौजूदगी



रिपोर्ट: काज़ी अमान, बीड
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ा गया है। इसी के तहत रविवार को महाराष्ट्र के बीड जिले के मोमिनपुरा बायपास स्थित इज्तेमागाह मैदान में एक भव्य जन विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्र हुए।
सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी

ने कहा,
यह लड़ाई सिर्फ एक कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक और संवैधानिक आज़ादी की रक्षा के लिए है। जब तक हम एकजुट हैं, केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेना ही पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस विधेयक को पूरी तरह खारिज करता है और देशभर में लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध जारी रहेगा।
व्यासपीठ पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ

बोर्ड के सचिव मौलाना मोहम्मद उमरेन महफूज़ रहमानी, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. कासिम रसूल इलियास, मुफ्ती मोइजुद्दीन कासमी, मौलाना रफीउद्दीन अशरफ़ी, मौलाना अब्दुल मुजीब साहब, बीड वक्फ बचाव कमेटी और मजलिस उलेमा के पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।
सभा में मौलाना उमरेन महफूज़ रहमानी ने कहा,
हमारी लड़ाई किसी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह काले कानून के खिलाफ है। जब तक यह कानून वापस नहीं होता, तब तक हमारा विरोध

जारी रहेगा। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मुस्लिम समाज के साथ अन्य समुदायों की भागीदारी भी है।
डॉ. कासिम रसूल इलियास ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन कानून वक्फ सम्पत्तियों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन पर कब्ज़ा जमाने के लिए है। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में सरकार द्वारा वक्फ पोर्टल पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का दबाव बनाना अनुचित है।
उन्होंने साफ कहा:
जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं

आता, तब तक किसी भी वक्फ सम्पत्ति को वक्फ पोर्टल पर रजिस्टर न किया जाए।
सभा का समापन सामूहिक दुआओं के साथ हुआ और यह जन आंदोलन आगामी समय में और तीव्र रूप लेने जा रहा है। बीड जिले के कोने-कोने से आए हज़ारों मुस्लिम नागरिकों की सहभागिता ने यह साबित कर दिया कि मुस्लिम समाज वक्फ अधिकारों की रक्षा को लेकर एकजुट है और किसी भी कीमत पर अपने धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से समझौता नहीं करेगा।

इस वक्फ विरोधी संशोधन विधेयक के खिलाफ जो सामाजिक लहर उठी है, वह सिर्फ एक समुदाय की नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा की रक्षा का प्रतीक है। यह कानून सिर्फ वक्फ संपत्तियों का मसला नहीं है, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान, अधिकार और संस्कृति पर सीधा हमला है।
आज ज़रूरत है, कि सभी नागरिक-धर्म, जाति और पंथ से ऊपर उठकर-संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए आवाज़ उठाएं।

राष्ट्रवादी पार्टी से विधायक संग्राम
जगताप को निकाला जाए-पूर्व
नगरसेवक अशफाक इनामदार की मांग
मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का
लगाया आरोप, अजित पवार को लिखित शिकायत

बीड (प्रतिनिधि):
बीड के पूर्व नगरसेवक अशफाक इनामदार ने राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मांग की है कि विधायक संग्राम जगताप को राष्ट्रवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि संग्राम जगताप लगातार मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरतपूर्ण और विभाजनकारी भूमिका अपना रहे हैं, जो पार्टी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के खिलाफ है।
इनामदार ने कहा कि पिछले ५-६ महीनों से संग्राम जगताप खुले तौर पर आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और सार्वजनिक सभाओं में मुस्लिम समाज के प्रति घृणा फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। यह केवल समाज को बांटने की कोशिश नहीं बल्कि राष्ट्रवादी पार्टी की मूल विचारधारा के भी खिलाफ है।
उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा समता, बंधुता और सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है और किसी भी समुदाय विरोधी सोच का समर्थन नहीं करती। यह अजित दादा पवार और पार्टी की स्पष्ट नीति है। ऐसे में संग्राम जगताप जैसे नेताओं की पार्टी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
अशफाक इनामदार ने संग्राम जगताप के बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए ताकि राष्ट्रवादी पार्टी की धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक समरसता वाली छवि बनी रहे।

आरक्षण की निर्णायक लड़ाई के लिए मराठा समाज की मुंबई कूच
मुख्यमंत्री फडणवीस मराठाओं से टकराव न करें: मनोज जरांगे पाटील की सरकार को चेतावनी
२७ अगस्त को अंतरवाली सराटी से प्रस्थान, २९ अगस्त को आज़ाद मैदान में आंदोलन शुरू होगा

रिपोर्ट: काज़ी अमान, बीड
मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटील ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब यह अंतिम और आर-पार की लड़ाई होगी, और मराठा समाज बिना ओबीसी आरक्षण लिए मुंबई नहीं छोड़ेगा।
बीड जिले के अंतरवाली सराटी गांव में आयोजित राज्यव्यापी मराठा समाज की विशाल बैठक को संबोधित करते हुए जरांगे पाटील ने सरकार को चेतावनी दी कि हमने दो साल इंतजार किया, अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मराठा समाज से टकराव नहीं करना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि २९ अगस्त को मुंबई के आज़ाद मैदान में बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए २७ अगस्त को अंतरवाली सराटी से मुंबई के लिए कूच किया जाएगा।
जरांगे पाटील ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण



होगा। हम मुख्यमंत्री के दुरमन नहीं हैं। लेकिन यदि आंदोलन के दौरान किसी मराठा को चोट पहुंची, तो राज्यभर की सड़कें बंद कर दी जाएंगी।
उन्होंने यह भी कहा:
अब कोई समझौता नहीं, आरक्षण सिर्फ ओबीसी श्रेणी में ही चाहिए। ५८ लाख जातीय प्रमाणपत्रों की जांच हो चुकी है, और ४ करोड़ मराठाओं का आरक्षण में समावेश हो सकता है। इसलिए अब गांव-गांव से लोग मुंबई पहुंचने की तैयारी करें। मुंबई में गुलाल उड़ा बिना कोई वापस नहीं लौटेंगा।
जरांगे पाटील ने आंदोलन में भाग लेने के लिए गांवों में स्थानीय नेताओं को सक्रिय होने का आग्रह किया और

कहा:
जो नेता आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, उन्हें चुनाव में हारना तय मानो। जो दिखाई देगा वही अपना है, जो नहीं दिखाई देगा वो अपना नहीं।
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो वर्षों में पहली बार अंतरवाली सराटी में मिलने की कोशिश की है। अगर हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं, तो हम मुंबई में आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं होतीं, तो आज़ाद मैदान में आर-पार की लड़ाई होगी।
जरांगे पाटील की प्रमुख मांगें: मराठा-कुणबी एक ही जाति घोषित हो, इसके लिए सरकार ऋ

निकाले
हैदराबाद, सातारा और बॉम्बे गजेटियर के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए
मराठा आंदोलन में दर्ज केस वापस लिए जाएं
आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी और मुआवज़ा दिया जाए
शिंदे समिति को एक वर्ष की समयवृद्धि दी जाए
जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा
विशेष जानकारी - आंदोलन का रूट प्लान:
२७ अगस्त, सुबह १० बजे:

अंतरवाली सराटी से प्रस्थान
२८ अगस्त: मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचना
२९ अगस्त: आज़ाद मैदान में आंदोलन की शुरुआत
यात्रा मार्ग: अंतरवाली सराटी फ शहागड फ पैठण फाटा फ पैठण फ शेवगांव फ अहमदनगर चौक फ पांढरी पुल फ आळाफाटा फ शिवनेरी किला फ वाशी फ चेंबूर फ मंत्रालय फ आज़ाद मैदान
संपादकीय टिप्पणी:
मनोज जरांगे पाटील द्वारा दिया गया यह आंदोलन का आह्वान मराठा समाज की अस्मिता और अधिकार की लड़ाई को नई दिशा देने जा रहा है। सरकार के लिए यह आखिरी चेतावनी की तरह है - या तो ठोस निर्णय लिया जाए या फिर जन आक्रोश के लिए तैयार रहा जाए।
अब देखना यह है कि मुंबई की सड़कों पर यह गुलाल सरकार को झुकने पर मजबूर करता है या फिर एक नए टकराव का संकेत बनता है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश



धनंजय मुंडे का गंभीर आरोप: विजय पवार को संदीप क्षीरसागर का संरक्षण, SIT जांच की मांग

बीड, २९ जून (प्रतिनिधि): उमाकिरण शैक्षणिक संकुल में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक धनंजय मुंडे ने बीड के विधायक संदीप क्षीरसागर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी विजय पवार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उसे शिवजयंती समिति का अध्यक्ष भी संदीप क्षीरसागर ने ही नियुक्त किया था। ऋषट् दर्ज होने के बाद भी संदीप क्षीरसागर आरोपी के साथ दिखाई दिए, जो उनके आपसी संबंधों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। ये संबंध केवल राजनैतिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी हो सकते हैं, ऐसा तीखा आरोप धनंजय मुंडे ने पत्रकार परिषद में लगाया। धनंजय मुंडे ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उमाकिरण शिक्षण संकुल की यह घटना अकेली नहीं हो सकती, बल्कि इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी होंगी, ऐसा संदेह व्यक्त किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी विजय पवार कम फीस का लालच देकर छात्राओं को बहकाने का काम कर रहा था। मुंडे ने कहा कि विजय पवार को यह सब करने की ताकत उसे मिले राजनीतिक समर्थन से मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि बीड के स्थानीय विधायक संदीप क्षीरसागर ने ही विजय पवार को ताकत दी। मुंडे ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी कि अपराध दर्ज होने के दिन के आरोपी और विधायक संदीप क्षीरसागर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (उउठ) सार्वजनिक किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पुलिस जांच कर रही है, उससे आरोपी को सजा मिलना मुश्किल लग रहा है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (डब्लूड) के माध्यम से की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री से मांग करेंगे।

हिंदी भाषा विवाद पर सरकार का यू-टर्न: दोनों जीआर रह, त्रिभाषा नीति पर अध्ययन के लिए नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में समिति गठित

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई
मुंबई: राज्य सरकार द्वारा पहली कक्षा से हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने के फैसले का मनसे और महा विकास आघाड़ी द्वारा तीव्र विरोध किए जाने के बाद अब सरकार ने इस पर एक कदम पीछे खींच लिया है। हिंदी को लेकर जारी किए गए दोनों शासन निर्णय (जीआर) को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को पत्रकार परिषद में घोषणा की कि त्रिभाषा नीति पर अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। पावसाळी अधिवेशन की पूर्व संध्या पर रविवार को मंत्रिमंडल की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ५ जुलाई को त्रिभाषा नीति के विरोध में प्रस्तावित मोर्चे और बढ़ते जन आक्रोश पर चर्चा हुई। आज आज़ाद मैदान में महाविकास आघाड़ी के नेताओं, जिनमें उद्धव ठाकरे प्रमुख थे, ने इन दोनों जीआर की होली जलाकर विरोध दर्ज कराया। इसके मद्देनज़र सरकार ने दोनों शासन निर्णयों को रद्द करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा: त्रिभाषा नीति के तहत तीसरी भाषा कौन सी हो, किस कक्षा से लागू हो, छात्रों को क्या विकल्प दिए जाएं - इन सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

जाधव पूर्व कुलगुरु और योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं। समिति के अन्य सदस्यों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। इस समिति की रिपोर्ट के बाद ही त्रिभाषा नीति लागू की जाएगी। फडणवीस ने आगे स्पष्ट किया: १६ अप्रैल २०२५ और १७ जून २०२५ को जारी किए गए दोनों शासन निर्णयों को रद्द किया जा रहा है। हमारे लिए मराठी भाषा और मराठी विद्यार्थी सर्वोपरि हैं। छात्र केंद्रित नीति हमारा ध्येय है, और इस विषय को लेकर हम राजनीति नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र जाधव समिति द्वारा पूर्व माशेलकर समिति की सिफारिशों का भी अध्ययन किया जाएगा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। ५ जुलाई का मोर्चा रद्द राज्य सरकार द्वारा पहली कक्षा से तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने वाला शासन निर्णय रद्द किए जाने के बाद, मनसे द्वारा ५ जुलाई को प्रस्तावित मोर्चा रद्द कर दिया गया है। आज आज़ाद मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे और महा विकास आघाड़ी के अन्य नेताओं ने दोनों जीआर की होली जलाकर विरोध जताया था। मनसे ने कहा कि मराठी समाज की एकता और संघर्ष की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा, इसलिए मोर्चा निकालने की आवश्यकता नहीं रही।

जालना में ऐतिहासिक वक्फ संरक्षण सम्मेलन का आयोजन हिंदू, मुस्लिम नेता का भी सहयोग



जालना:(संवाददाता)सभी संगठनों, जमातों, उलमा-ए-किराम और आम-खास की सामूहिक कोशिशों से जालना में वक्फ संरक्षण का ऐतिहासिक सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। एक लाख से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराकर वर्तमान सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब हिंदुस्तान के मुसलमान सरकार के जुल्म और नाइंसाफी को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह विशाल सम्मेलन हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में आयोजित हुआ।सम्मेलन में विपक्षी दलों के नेताओं जैसे सांसद कल्याण काले, एनसीपी के पूर्व राज्य मंत्री राजेश टोपे, कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश गोरंटियाल, और शिवसेना यूबीटी के भास्कर अंबीकर ने अपने भाषणों में वक्फ कानून के खिलाफ अपनी समर्थन की बात कही। इसके अलावा, उलमा-ए-किराम में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी (अध्यक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड), मौलाना मोहम्मद उमैरिन महफूज रहमानी (सचिव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड), मुफ्ती मुअज्जुद्दीन कासमी (सदस्य, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड), कासिम रसूल इलियास (संयोजक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड), मौलाना रफीउद्दीन अशरफी (सदस्य, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड), जियाउद्दीन इस्लाही (वहदत-ए-इस्लामी), अजहर एडवोकेट (एसडीपी), मुफ्ती अब्दुलहमान (काजी-ए-शरीयत, जालना), मौलाना सैयद नसरुल्लाह हुसैनी सुहैल नदवी (नकीब, अमरत-ए-शरिया, जालना), और शेख मुजीब (सचिव, जमात-ए-इस्लामी, महाराष्ट्र) ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विशेष रूप से, सम्मेलन के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना उमैरिन महफूज रहमानी ने स्पष्ट किया कि सरकार को होश में आना चाहिए। अगर सरकार इन विरोधी कदमों और सम्मेलनों के बाद भी वक्फ कानून वापस नहीं लेती, तो बोर्ड भविष्य में और सख्त कदम उठा सकता है।सम्मेलन में लोगों का सैलाब उमड़ा। इंद्याह मैदान खचाखच भरा था, और बाहर की सड़कें भी प्रतिभागियों के लिए अपर्याप्त साबित हो रही थीं। एक ओर युवाओं ने ट्रैफिक को संभाला, तो दूसरी ओर दूसरी टीम ने सुरक्षा, नमाज और भीड़ को नियंत्रित करने का जिम्मा संभाला। कुछ युवा आसपास

से आए सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन की व्यवस्था में जुटे थे।कार्यक्रम की निजामत मुफ्ती फहीम, लियाकत अली खान यासर, मोहम्मद कासिम एजाज सिद्दीकी और इस्माइल सर ने बेहद व्यवस्थित ढंग से निभाई। इससे पहले हाफिज कारी मोहम्मद मुअज ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तराना मधुर अंदाज में पेश किया।इसी दिन दोपहर २ से ४ बजे तक सिटी लॉन्स में महिलाओं का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मौलाना उमैरिन महफूज रहमानी ने व्यापक भाषण दिया। इस सम्मेलन में सात हजार महिलाओं ने भाग लिया।कार्यक्रम को सफल बनाने में वक्फ संरक्षण समिति और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जालना के सदस्यों, जैसे मुफ्ती अब्दुलहमान (काजी-ए-शरीयत, जालना), मौलाना अब्दुलरुफ नदवी (संयोजक), मौलाना सैयद नसरुल्लाह झेग्रश (नकीब, अमरत-ए-शरिया, जालना), मुजीब सर (सचिव, जमात-ए-इस्लामी, महाराष्ट्र), मुफ्ती फहीम, बड़े कद के नेता इकबाल पाशा, मुफ्ती फारूक, मुफ्ती मोहम्मद इलियास नदवी, इस्माइल सर (अमीर, जमात-ए-इस्लामी), शाकिर सर (नाजिम-ए-

इलाका), फीरोज अली (मौलाना मुस्लिम विकास परिषद), लियाकत अली खान यासर, असदुल्लाह रिजवी, उतीक खान, अहमद नूर सर, उर्फान कैप्टन, मौलाना ईसा खान काशफी, मस्जिदों के इमाम और मकतबों के शिक्षकों की अथक मेहनत शामिल रही।शहर के गणमान्य व्यक्तियों में शाह आलम खान, पत्रकार अब्दुल हफीज, मोहम्मद अयूब खान, बदर चौंस, शेख माजिद (एमआईएम), एडवोकेट अमजद, अक्बर खान, डॉ. अजीम, सुहैल कादरी, फीरोज तंबोली, अब्दुल हमीद, अजहर काउंसलर, वाजिद खान काउंसलर, एडवोकेट अशफाक, शकील काउंसलर, शेख वसीम, मझर बिल्डर, शाकिर खान, नजीब सर काउंसलर, सलीम भाई, उर्फ काउंसलर और अन्य कई लोगों ने हर तरह से सहयोग किया।लोगों के बीच चर्चा है कि जालना के इतिहास में यह पहला ऐसा सम्मेलन था, जिसमें इतना विशाल जमैसैलाब उमड़ा। सभी जमातों, संगठन और जिले के लोग एक मंच पर आए और इस सम्मेलन को सफल बनाया। आसपास के क्षेत्रों से भी हजारों लोगों ने भाग लिया, और उस दिन लोगों ने अपने कारोबदार भी बंद रखे।

गुलाम साकिब को ‘डॉ. अब्दुल क़ादिर फारूकी राष्ट्रीय उर्दू पुरस्कार’ से नवाज़ा गया

जज डॉ. ख्वाजा फारूक़ अहमद बोले-साकिब की रचनाएँ पाठकों से संवाद करती हैं, वे एक बहुआयामी शख्सियत हैं

बीड (प्रेस नोट): भारतीय उर्दू विकास फाउंडेशन, सोलापुर की ओर से बीड के मोहिब-ए-उर्दू हॉल में आयोजित एक भव्य और विद्वतजनों से भरपूर समारोह में युवा शायर, लेखक और शिक्षाविद गुलाम साकिब (पूरा नाम: शेख अब्दुलहीम मुहीउद्दीन) को 'डॉ. अब्दुल क़ादिर फारूकी राष्ट्रीय उर्दू पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सेशन जज डॉ. ख्वाजा फारूक़ अहमद (परांडा, ज़िला उस्मानाबाद) के करकमलों से प्रदान किया गया। इस अवसर पर जज डॉ. ख्वाजा फारूक़ अहमद ने कहा, गुलाम साकिब की रचनाएँ जीवन के अनुभव और समाज की आलोचना को आत्मसात किए हुए हैं। वे एक लेखक, कवि, पत्रकार और शिक्षक - चारों रूपों में सक्रिय हैं। उनकी किताब 'किरदार' पढ़ने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि उनकी लेखनी में पाठक अपने आप को महसूस करता है। उन्होंने आगे सलाह देते हुए कहा, साकिब को आत्ममूल्यांकन करना चाहिए और दिखावे से दूर रहते हुए संक्षिप्तता को अपनाना चाहिए। उम्मीदों से अधिक उम्मीदें न रखें ताकि टूटने का डर न रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय उर्दू विकास फाउंडेशन सोलापुर के अध्यक्ष, वरिष्ठ अफ़सानानिगर सुल्तान अख्तर ने पुरस्कार की महत्ता और डॉक्टर अब्दुल क़ादिर फारूकी की अमेरिका में उर्दू भाषा के लिए की गई सेवाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा: गुलाम साकिब एक सशक्त लेखक, शायर, समीक्षक, आलोचक और रेखाचित्र लेखक हैं। उन्होंने ९ पुस्तकें लिखी हैं और इस पुरस्कार के लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं। सम्मान समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की टिप्पणियाँ - सिनियर पत्रकार एवं शिक्षा-प्रेमी अय्यूब नलामंडो (सोलापुर): साकिब से विशेष लगाव है, उनका साहित्य परिचय का मोहताज नहीं। मशहूर हास्य लेखक मंज़ूर बकार (गुलबर्गा): गुलाम साकिब एक परिपक्व और प्रभावशाली लेखक हैं। श. शकील (औरंगाबाद): वे तेज़ी से साहित्य में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं।



डॉ. शौकतुल्लाह हुसैनी (वाइस प्रिंसिपल, मोलिया सीनियर कॉलेज, बीड): साकिब ने शॉर्टकट से दूर रहकर केवल काम पर फोकस किया, वे सादगी और ईमानदारी की मिसाल हैं। प्रो. अब्दुल अनीस (हेड, इंग्लिश डिपार्टमेंट, मोलिया कॉलेज): वे मेरे विद्यार्थी हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रो. सैयद फरीद अहमद नहरी: साकिब कभी किसी अच्छे कार्य के लिए मना नहीं करते, यही उनकी विशेषता है। नदीम मिर्ज़ा (चीफ़ एडिटर 'जमाल' व 'शहरनामा'): साकिब ने खुद को पहचान लिया है, उन्हें अब धोखेबाज़ों से बचना चाहिए। डॉ. जोशी (मराठी कवि): वे शब्दों के ज़रिए लोगों को अपना बना लेने वाले शायर हैं। सादोलकर (मराठी कवि): साकिब दिलों पर राज करते हैं। अनवर पाशा (सामाजिक कार्यकर्ता): साकिब पानी जैसे हैं - हर रंग को अपनाने की क्षमता रखते हैं। मुस्तफा खान (जमीयत-उलमा नेता): वे सदैव अच्छे कार्यों में अग्रणी रहते हैं। जावेद पाशा (पत्रकार): गुलाम साकिब इस पुरस्कार के सच्चे हकदार हैं। शेख कलाम (शिक्षाविद): ऐसे लोगों की हिफ़ाज़त ज़रूरी है ताकि आने वाली नरस्लें लाभ उठा सकें। काज़ी मुजीबुलहमान: साकिब की पहचान

करने वाले मुस्ताफ़ अनसारी जैसे लोग असली जौहरी हैं। एलियास इनामदार: बीड को उन पर गर्व है। मुमिन इसहाक (प्रेसिडेंट, उर्दू क्लब): साकिब बे-लौस तौर पर उर्दू और क़ौम की सेवा में लगे हैं। डॉ. इमरान खान (प्रिंसिपल, शाहीन अकैडमी): अगर साकिब अवसरवादी होते, तो आज महल में रहते। उर्दू समर्थक हुसैन अख्तर: उन्हें उर्दू अकैडमी का पुरस्कार मिलना चाहिए। मुख्य अतिथियों में शामिल थे: जज डॉ. ख्वाजा फारूक़ अहमद, मुस्ताफ़ अनसारी (सचिव, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी), मंज़ूर बकार

(गुलबर्गा), अय्यूब नलामंडो (सोलापुर), श. शकील (औरंगाबाद), सुल्तान अख्तर (सोलापुर), मुजीब खान (कोच, गुलबर्गा), नदीम मिर्ज़ा (बीड), डॉ. शोकत हुसैनी, प्रो. सैयद फरीद, प्रो. अनीस, डॉ. जुबैर हुसैनी, डॉ. इमरान खान, काज़ी मुजीबुलहमान, इंजीनियर अजहर इनामदार, पत्रकार जावेद पाशा, और अन्य नामचीन शख्सियतें। कार्यक्रम का कामयाबी के लिए खास योगदान: मोहिब-ए-उर्दू शेख मुख्तार कांटेक्टर, जाहिद हुसैन (प्रिंसिपल, मिल्लत स्कूल), आफरीन मेडम, सिद्दीक साया एजुकेशन, रिज़वान खान, अरहम व अर्सल साबरी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। गुलाम साकिब ने अपने वक्तव्य में कहा: आप सबकी मौजूदगी ही मेरी असली दौलत है। मेरे जैसे व्यक्ति के पास आप जैसे सच्चे और ईमानदार साथी हैं, यही मेरी असल अमीरी है। जज साहब की एक-एक बात मेरे लिए पुरस्कार से कम नहीं। सुल्तान अख्तर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की।